मंजूनाथ आनंदप्पा उर्फ शिवप्पा हनासी

बनाम

तम्मनासा और अन्य

13 मार्च, 2003

[बृजेश कुमार और एस.बी. सिन्हा, जे.जे.]

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 धारा 16(सी) और धारा 20: संविदा की विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद - विचारण न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वादी द्वारा संविदा के अपने भाग के पालन के लिए अपनी तत्परता और इच्छा साबित नहीं की गई - प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया - द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया - द्वितीय अपील में - अभिनिर्धारित किया गया: वादी ने ना तो वाद की संपत्ति के स्वामी से विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए कहा और ना ही निर्धारित अवधि के भीतर उसके पक्ष में शेष राशि जमा करने के लिए कहा - इस प्रकार, वादी यह दर्शित करने और साबित करने में विफल रहा कि वह संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए तत्पर और इच्छुक था - इसलिए अधिनियम के आज्ञात्मक प्रावधान की पालना नहीं करने के कारण संविदा की विनिर्दिष्ट पालना उसके पक्ष में नहीं करवायी जा सकती है - सिविल प्रक्रिया संहिता, परिशिष्ट ए का फॉर्म 47 एवं 48।

धारा 20 - विवेकाधीन अनुतोष - अनुदत्त - अभिनिर्धारित: वादी ने ना तो मालिक द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित करवाने का कोई प्रयास किया और ना ही अनुतोष प्राप्त करने के लिए युक्तियुक्त समय के भीतर न्यायालय में पहुंचा, इसलिए वह विवेकाधीन अनुतोष का हकदार नहीं है।

शब्द और वाक्यांश: ‘‘तत्पर और इच्छुक‘‘ - विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16(सी) के संदर्भ में अर्थ।

प्रतिवादी संख्या 1 - मालिक ने वाद संपत्ति के संबंध में वादी के साथ 01.10.1978 को 30,000/- रुपये की प्रतिफल राशि के लिए एक करार किया था, जिसमें से 20,000/- रुपये अग्रिम के रूप में इस शर्त के साथ भुगतान किया गया था कि शेष राशि का भुगतान करने पर, विक्रय कर दिया जाएगा। करार की दिनांक से 3 वर्ष के भीतर विक्रय-विलेख निष्पादित किया जाना था। हालाँकि, वादगत संपत्ति के स्वामी ने 15.05.1984 को वादगत संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को 50,000/- रुपये में बेच दी; वादी ने 08.08.1984 को वादगत संपत्ति के स्वामी को नोटिस देकर दिनांक 01.10.1978 को हुए विक्रय करार के विनिर्दिष्ट पालन की मांग की और न्यायालय में विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक वाद भी संस्थित किया। विचारण न्यायालय ने वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी ने अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा का जिक्र नहीं किया और अपने आचरण से संतुष्ट नहीं होने पर विवेकाधीन राहत देने से भी इन्कार कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निष्कर्षों की पुष्टि की। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील में इसे उलट दिया। इसलिए व्यथित विक्रेता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि वादी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 (सी) के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान का अभिवचन

करने में विफल रहा है, उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर निचली अदालतों के फैसले को उलटने में गलती की है कि विक्रेता ने वाद में प्रतिवाद नहीं किया था। चूंकि निचली अदालतों ने अधिनियम की धारा 20 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया, इसलिए उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था; और यह कि वाद युक्तियुक्त समय के भीतर दायर नहीं किया गया था।

प्रत्यर्थी की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया कि वाद में एवं अभिसाक्ष्य में किए गए कथनों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वादी प्रतिफल की शेष राशि का भुगतान करने के लिए तैयार था, प्रावधान का सारभूत रूप से अनुपालन किया गया है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए,

अभिनिर्धारित किया: 1.1: करार दिनांक 01.10.1978 को या इसके आसपास हुआ था। वादपत्र में अंकित अस्पष्ट कथनों के अलावा, वादी ने यह दर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं पेश की है कि किसी भी समय और उक्त समझौते की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के भीतर, उसने कभी भी प्रतिवादी संख्या 1, वादगत संपत्ति के स्वामी को अपने पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने या प्रतिफल की शेष राशि उसे सौंपने के लिए कहा। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 (सी) के तहत प्रावधान के संदर्भ में, वादी पर यह दर्शित करने और साबित करने का दायित्व है कि वह अनुबंध की आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए हमेशा

तत्पर और इच्छुक था, जो कि उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाना आवश्यक था।

1.2. वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के परिशिष्ट ए के फॉर्म 47 और 48 के अनुसार कोई प्रकथन नहीं किया है, जो उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें वादी द्वारा ऐसे प्रकथन करने की आवश्यकता होती है। इस तथ्य के अलावा कि कथित मांग की दिनांक का खुलासा नहीं किया गया है, माना जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 पर ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। यद्यपि वादी ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किये गए अटॉर्नी को रद्द कर दिया था, वादी ने अपने बयान में केवल यह कहा कि विक्रय करार के निष्पादित होने के बाद ऐसा निरसन हुआ। यदि वह इस तथ्य से अवगत था कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित अटॉर्नी की शक्ति रद्द कर दी गई थी, तो विक्रय करार के निष्पादन के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को लाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 पर उसके द्वारा किसी भी मांग का सवाल ही नहीं उठता। आगे, अविवादित रूप से उक्त मुख्त्यारनामा/पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत नहीं थी। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 2 उसके पक्ष में कोई पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित नहीं करवा सकता था। इस प्रकार, विक्रय के करार के संदर्भ में विक्रय विलेख को निष्पादित करवाने के लिए कोई भी मांग वादगत संपत्ति के स्वामी प्रतिवादी संख्या 1 से की जा सकती थी। शेष प्रतिफल राशि 10,000/- रुपये भी केवल प्रतिवादी संख्या 1 को दी जा

सकती था। कथित नोटिस 08.8.1984 को जारी किया गया था, यानी, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बहुत बाद, जिसके भीतर विक्रय के करार पर कार्रवाई की जानी आवश्यक थी। वादगत संपत्ति के संबंध में विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए 10,000/- रुपये की शेष राशि का भुगतान करने की इच्छा के संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपने बयान में दिए गए ये बयान विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 (सी) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।

1.3. संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक वाद में वादी को न केवल यह दलील देनी होगी कि वह हमेशा और यहां तक कि वाद दायर करने की दिनांक पर भी संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर और इच्छुक था, बल्कि इसे साबित भी करना होगा। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों में जहां अक्षरशः सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, लेकिन वाद में रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के साथ समग्र रूप से वादी में दिए गए सभी कथनों को पढ़ने से तत्परता और इच्छा का पता लगाया जा सकता है। वाद में, उक्त आशय के लिए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16(सी) की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन किया गया माना जा सकता है। मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि वादी ने कानून की आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से अनुपालन भी किया है।

ओसेफ वर्गीस बनाम जोसेफ एले और अन्य, [1969] 2 एस.सी.सी. 539; आर.सी. चंडीओक और अन्य बनाम चुन्नी लाल सबरवाल और अन्य, [1970] 3 एस.सी.सी. 140; अब्दुल खादर रॉथर बनाम पी.के. सारा बाई और अन्य, एआईआर (1990) एससी 682; सैयद दस्तगीर बनाम टी.आर. गोपालकृष्ण शेट्टी, [1999] 6 एस.सी.सी. 337; मोतीलाल जैन बनाम रामदासी देवी और अन्य, [2000] 6 एस.सी.सी. 420 और पुष्पारानी एस. सुंदरम और अन्य बनाम पॉलीन मनोमणि जेम्स और अन्य, [2002] 9 एस.सी.सी. 582, पर भरोसा किया गया।

किदार लाल सील और अन्य बनाम हरीलाल सेकल, [1952] एस.सी.आर. 179, प्रतिष्ठित.

2.1. वादी ने विक्रय का करार करने की दिनांक से लगभग छह वर्ष बाद वाद दायर किया। वह यह दर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं लाया कि उसने कभी भी प्रतिवादी संख्या 1, संपत्ति के मालिक, को विक्रय विलेख को निष्पादित करने के लिए कहा था। उसने तब वाद दायर किया जब उसे पता चला कि वाद की जमीन पहले ही अपीलार्थी के पक्ष में बेच दी गई थी। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 20 के संबंध में विवेकाधीन राहत प्राप्त करने के लिए वादी के लिए उचित समय के भीतर न्यायालय में जाना अनिवार्य था। उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए, वादी विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं था।

वीरायी अम्मल बनाम सीनी अम्मल, [2002] 1 एस.सी.सी. 134 एवं लूई मारी डेविड और अन्य बनाम लुईस चिन्नया अरोगियास्वामी और अन्य, [1996] 5 एस.सी.सी. 589, पर भरोसा किया गया।

2.2. विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने वादी के पक्ष में अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इन्कार कर दिया। उच्च न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था कि नीचे के न्यायालयों द्वारा गलत कानूनी सिद्धांत पर विवेक का प्रयोग किया गया है।

ललित कुमार जैन और अन्य बनाम जयपुर ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड, [2002] 5 एस.सी.सी. 383; उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बनाम सुंदर ब्रदर्स, एआईआर (1967) एससी 249 और गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड आदि बनाम गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा व अन्य, एआईआर (1980) एससी 1896, पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1998 की सिविल अपील संख्या 5662

(कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 1994 के आरएसए संख्या 677 में पारित आदेश और निर्णय दिनांकित दिनांक 18.03.1998 से अपील)

अपीलार्थीयों की ओर से - शांता कुमार महाले, राजेश महाले, के सी सुदर्शन और आर सी कोहली।

प्रत्यर्थी की ओर से - अमरेंद्र शरण एवं शंकर दिवते।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया।

प्रतिवादी संख्या 3 यहां अपीलार्थी है। प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकृत रूप से वादगत संपत्ति का स्वामी है। प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 का अटॉर्नी है, जिसने दिनांक 01.10.1978 को या उसके आसपास वादगत संपत्ति संख्या सी.टी.एस संख्या 1921/ए गडग बेटागेरी, सिटी नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में वादी के साथ विक्रय के लिए एक करार कुल 30,000/- रुपये के लिए किया था, जिसमें से 20,000/- रुपये की राशि कथित तौर पर अग्रिम के रूप में भुगतान की गई थी। उक्त समझौते के संदर्भ में, वादी को कथित तौर पर वादगत संपत्ति पर कब्जा दिया गया था।

उक्त विक्रय विलेख, को 10,000/- रुपये की शेष प्रतिफल राशि के भुगतान पर उसकी दिनांक से 3 वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाना था। प्रतिवादी संख्या 3, अपीलार्थी ने दिनांक 15.05.1984 को 50,000/- रुपये के मूल्यवान प्रतिफल के लिए पंजीकृत विक्रय-विलेख के आधार पर वाद संपत्ति खरीदी। वादी ने लगभग 15.05.1984 को वाद की संपत्ति का सी.टी.एस. विवरण प्राप्त करने के लिए सी.टी.एस. कार्यालय में पूछताछ की, जब उसे पता चला कि प्रतिवादी ने पहले ही वादगत संपत्ति के संबंध में एक पंजीकृत विक्रय विलेख अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित कर दिया है। जिसके बाद उसने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को दिनांक 08.08.1984 को एक नोटिस भेजकर दिनांक 01.10.1978 के उक्त विक्रय करार के विनिर्दिष्ट

पालन की मांग की। जहां तक वाद हेतुक का संबंध है, वादपत्र में यह कहा गया था:

> ‘‘इस वाद में वाद हेतुक दिनांक 8-8-1984 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादियों को नोटिस दिया, जिसमें दिनांक 1-10-1978 के करार के विनिर्दिष्ट पालन की मांग की गई और जब प्रतिवादी वादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने में विफल रहे।‘‘

यह विवादित नहीं है कि वादी ने अपने वादपत्र में करार के अपने भाग की पालना करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा के संबंध में कोई दावा नहीं किया है, जैसा कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16 (सी) के संदर्भ में अनिवार्य है। केवल आरोप लगाया है।

> ‘‘विक्रय करार के बाद, वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 से प्रतिवादी संख्या 1 को लाने और विक्रय की शेष प्रतिफल राशि प्राप्त करने के बाद एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने की मांग की। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 इसे एक के बाद एक कारण बताते हुए इसे टालता रहा। अंत में, वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को नोटिस देकर इसके संबंध में मांग की। प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रतिवादी संख्या 1 को भेजा गया नोटिस अदम तामील लौट आया।

नोटिस के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 वादी के पक्ष में वाद संपत्ति के संबंध में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करने में विफल रहे।''

स्वीकृत रूप से वादगत संपत्ति के मालिक, प्रतिवादी संख्या 1 को कोई नोटिस नहीं मिला।

विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया कि वादी ने वाद में करार के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा का उल्लेख नहीं किया है, वह अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री का हकदार नहीं है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने वादी के आचरण को ध्यान में रखते हुए, वादी के पक्ष में विवेकाधीन राहत देने से इन्कार कर दिया।

उक्त निर्णय की अपील पर प्रथम अपीलीय न्यायालय उक्त निष्कर्षों से सहमत था।

वादी द्वारा दायर द्वितीय अपील में, उच्च न्यायालय ने, यद्यपि, उक्त निष्कर्षों को उलट दिया। उसमें, कानून का एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनाया गया, वह करार के अपने भाग को पूरा करने के लिए वादी की ओर से तत्परता और इच्छा दर्शित किये जाने के संबंध में था। उच्च न्यायालय ने उक्त प्रश्न का उत्तर केवल यह कहते हुए दिया: ''जो कानून का प्रश्न बनाया गया था, वह वादी की ओर से अनुबंध/करार के अपने हिस्से को पूरा करने की इच्छा और तत्परता के संबंध में था। लेकिन यह प्रश्न

साधारण कारण से विचार के लिए नहीं उठता है प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने मामले का विरोध नहीं किया। हालांकि, इसमें यह प्रश्न शामिल हो गया कि क्या यहां अपीलार्थी मूल्य के लिए एक सदभाविक क्रेता था। उक्त प्रश्न का उत्तर केवल इस आधार पर नकार दिया गया था कि अपीलार्थी ने वाद में स्वयं को परीक्षित नहीं करवाया था।"

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महाले ने इस अपील के समर्थन में एक संक्षिप्त प्रश्न उठाया है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा का उल्लेख करने में विफल रहा और/या उपेक्षा की, उच्च न्यायालय को माना जाना चाहिए कि उसने विवादित निर्णय पारित करने में इस आधार पर गलती की है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद में प्रतिवाद नहीं किया। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16(सी) के संदर्भ में कथन किया जाना आज्ञापक है। इस संबंध में [1999] 6 एस.सी.सी 337 सैयद दस्तगीर बनाम टी आर गोपालकृष्ण सेट्टी पर निर्भरता है।

विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि, किसी भी घटना में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय अदालत ने उक्त अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री मोहले ने निवेदन किया कि यद्यपि समय अनुबंध का सार नहीं है, लेकिन वादी की ओर से उचित समय के भीतर वाद दायर करना अनिवार्य है। इस संबंध में केएस विद्यानदम और अन्य बनाम वैरावन [1997] 3 एस.सी.सी. 1 पर भरोसा रखा गया है।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमरेंद्र शरण यह प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा वाद के पैराग्राफ 6 में किये गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, साथ ही उसके बयान में भी जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन भी वह प्रतिवादियों को शेष राशि का भुगतान करने के लिए तैयार थे, यह माना जाना चाहिए कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16 (सी) की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन देखा गया है। उक्त तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने मोतीलाल जैन बनाम रामदासी देवी और अन्य, [2000] 6 एस.सी.सी. 420 पर मजबूत भरोसा प्रकट किया।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे आग्रह किया कि अभिवचनों का सख्त अर्थान्वयन नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में किदार लाल सीलैंड अन्य बनाम हरि लाल सील, [1952] एस.सी.आर. 179 पर भरोसा रखा गया था।

मामले का मूल तथ्य विवाद में नहीं है। यह करार 01.10.1978 को या इसके आसपास हुआ था। जैसा कि यहां पहले देखा गया है, वादी के पैरा संख्या 6 में दिए गए अस्पष्ट कथनों के अलावा, वादी ने यह दिखाने

के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी है कि किसी भी समय और उक्त समझौते की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के भीतर उसने कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 से अपने पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए कहा या प्रतिफल की शेष राशि उसे संदत्त करने को कहा। वादी ने स्वीकार किया कि अकेले प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 08.08.1984 को एक नोटिस दिया गया, जो कि 3 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के काफी बाद है। जब उसे पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलार्थी के पक्ष में संपत्ति हस्तांतरित कर दी है, तो उसने वाद दायर किया। स्वीकृत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई नोटिस नहीं मिला।

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16(सी) इस प्रकार है:

> "किसी संविदा का विशिष्ट पालन किसी व्यक्ति के पक्ष में लागू नहीं किया जा सकता:-
>
> .....जो यह दर्शित करने और साबित करने में विफल रहता है कि उसने संविदा की उन आवश्यक शर्तों का पालन किया है या करने के लिए हमेशा तत्पर और इच्छुक रहा है, जिनका पालन उसके द्वारा पूरा किया जाना है, उन शर्तों के अलावा जिनके निष्पादन को प्रतिवादी द्वारा रोका या माफ कर दिया गया है।"

उपरोक्त वर्णित प्रावधान के संदर्भ में, वादी पर यह कथन करना और साबित करना अनिवार्य है कि वह अनुबंध की उन आवश्यक शर्तों को पूरा

करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक था, जिनका पालन उसके द्वारा किया जाना आवश्यक था।

सिविल प्रक्रिया संहिता के परिशिष्ट ए के फॉर्म 47 और 48 उस तरीके को निर्धारित करते हैं जिसमें वादी द्वारा इस तरह के दावे किए जाने की आवश्यकता होती है। निर्विवाद रूप से, वादी ने इस आशय का कोई दावा नहीं किया है। उसने, जैसा कि यहां पहले देखा गया, केवल यह तर्क दिया कि उसने प्रतिवादी संख्या 2 को एक पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को लाने के लिए कहा था। इस तथ्य के अलावा कि कथित मांग की दिनांक का खुलासा नहीं किया गया है, माना जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 पर ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। इस समय, हम देख सकते हैं कि वादी ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर दिया था। अपने बयान में, उसने केवल यह कहा कि विक्रय के करार के निष्पादित होने के बाद ऐसा निरसन हुआ। यदि वह इस तथ्य से अवगत था कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दी गई थी, तो विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को लाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 पर उसके द्वारा किसी भी मांग का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा, निर्विवाद रूप से उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत नहीं थी। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 2 उसके पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित नहीं

कर सका। इस प्रकार, विक्रय करार के संदर्भ में विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए मांग, यदि कोई हो, केवल प्रतिवादी संख्या 1, संपत्ति के मालिक पर की जा सकती थी। 10,000/- रुपये का शेष प्रतिफल भी प्रतिवादी संख्या 1 को ही दिया जा सकता था। जैसा कि यहां पहले बताया गया है, कथित नोटिस 08.08.1984 को जारी किया गया था, यानी तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के काफी बाद, जिसके भीतर करार हुआ था।

अपने बयान में भी, उसने केवल इतना कहा - ''करार के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 ने विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया। मैंने एक नोटिस जारी किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को शेष राशि प्राप्त करने के बाद विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए कहा गया। हालांकि वे नोटिस प्राप्त होने के बावजूद विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए आगे नहीं आए। आज भी मैं शेष 10,000/- रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार हूं।'' ये कथन विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16(सी) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16(सी) के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता ओसेफ वर्गीस बनाम जोसेफ एले और अन्य, [1969] 2 एस.सी.सी. 539 में इस न्यायालय के विचार के लिए आई थी जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था:

> ".....वादी ने ना तो वादपत्र में और ना ही किसी बाद के प्रक्रम पर यह अनुरोध किया कि वह प्रतिवादी के लिखित

बयान में किए गए समझौते को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक है। विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए एक वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रथम अनुसूची के फॉर्म 47 और 48 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। विशिष्ट निष्पादन के लिए एक वाद में वादी पर यह दायित्व नहीं है कि वह न केवल उस समझौते को निर्धारित करे जिसके आधार पर वह उसके सभी विवरणों पर वाद करता है, बल्कि उसे आगे बढ़कर यह दलील भी देनी होगी कि उसने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत समझौते को पूरा करने के लिए विशेष रूप से आवेदन किया है। लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा नहीं किया है। उसे आगे यह दलील देनी होगी कि वह समझौते में अपने हिस्से का विशेष रूप से पालन करने के लिए तैयार है और अभी भी तैयार है। ना तो वादपत्र में और ना ही वाद के किसी भी बाद के चरण में वादी ने उन दलीलों को स्वीकार किया है। जैसा कि इस न्यायालय ने पंडित प्रेम राज बनाम डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट) (लिमिटेड) और अन्य में देखा, (सिविल अपील संख्या 37/66, 04.04.1968 को निर्णीत) [1968 (3) एस.सी.आर. 648] यह अच्छी तरह से निश्चित है कि विनिर्दिष्ट अनुपालन के वाद में वादी को यह कथन करना चाहिए कि वह अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के

लिए तैयार और इच्छुक है और इस तरह के कथन के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है।"

हालाँकि, उक्त निर्णय पर ध्यान दिए बिना, आर सी चंडियोक और अन्य बनाम चुन्नी लाल सभरवाल और अन्य में दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने [1970] 3 एस.सी.सी. 140 में कहा:

"6.....तत्परता और इच्छा को एक सीधे-सीधे फार्मूले के रूप में नहीं माना जा सकता है। इन्हें संबंधित पक्ष के इरादे और आचरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों से निर्धारित किया जाना चाहिए। हमारे फैसले में इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि अपीलार्थी किसी भी स्तर पर अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं थे।"

अब्दुल खादर रोथर बनाम पी.के. सारा बाई और अन्य, एआईआर 1990 एससी 682, इस न्यायालय ने ओसेफ वर्गीस (सुप्रा) के कथन का पालन किया:

"उनके वादपत्र में विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री प्राप्त करने के लिए आवश्यक अपेक्षित दलीलें शामिल नहीं हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त यह

न्यायसंगत उपाय ऐसी दलीलों और सबूतों के आधार पर नहीं मिल सकता है।''

[1999] 6 एस.सी.सी. 337 सैयद दस्तगीर बनाम टी आर गोपालकृष्ण सेट्टी मामले में यह प्रश्न फिर से इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया।

इसमें अब्दुल खादर रोथर (सुप्रा) और ओसेफ वर्गीस (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसलों का भी उल्लेख नहीं किया गया था। हालाँकि, अन्य बातों के साथ-साथ आर सी चंडियोक (सुप्रा) पर ध्यान देते हुए, इस न्यायालय ने कहा:

''13. आर सी चंडियोक बनाम चुन्नी लाल सभरवाल, [1970] 3 एस.सी.सी. 140 के मामले में यह माना गया था कि तत्परता और इच्छा को स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसे संबंधित पक्ष के इरादे और आचरण से संबंधित परिस्थितियों व संपूर्ण तथ्यों से निर्धारित किया जाना चाहिए। अंत में, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वादी द्वारा की गई दलील ना केवल अनुबंध के तहत दायित्व के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए उसकी तत्परता और इच्छा को दर्शाती है, बल्कि कुल मिलाकर राशि से पता चलता है कि उसने अपने दायित्व का हिस्सा पूरा कर लिया है। हम इस तरह की

याचिका को धारा 16 (सी) के तहत आवश्यक ''तत्परता और इच्छा'' की दलील भी मानते हैं। उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने उक्त धारा के संदर्भ में वादी की याचिका की गलत व्याख्या के आधार पर उसके दावे को विफल करके एक त्रुटि की है।''

उस मामले में वादी के वादपत्र में अपेक्षित कथन निम्नलिखित प्रभाव वाले थेः

''6.... प्रतिवादी ने 01.08.1960 को वादी के साथ एक करार किया.... 9500/- रुपये के प्रतिफल के लिए..... वादी उस पर बंधक राशि के समायोजन पर सहमत हुआ और बिक्री मूल्य के अग्रिम भुगतान के लिए 500/- रुपये का भुगतान किया गया, कि 4000/- रुपये और उससे अधिक की प्राप्त राशि के भुगतान पर, वह वाद अनुसूची संपत्तियों को बताते हुए एक उचित बिक्री विलेख निष्पादित करेगा; प्रतिवादी को तदनुसार 3680/- रुपये की राशि प्राप्त हुई है..... वादी से और 21.12.1965 को समझौते पर इसका पृष्ठांकन किया है। उसे 21.03.1966 को 100/- रुपये और 04.05.1966 को 100/- रुपये और कुल मिलाकर 3880/- रुपये प्राप्त हुए हैं। ये भुगतान प्रतिवादी की खाता-बही में भी विधिवत लिखा गया है। वादी ने बिक्री मूल्य के

लिए 120/- रुपये की शेष राशि प्राप्त करने और उचित बिक्री निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी से संपर्क किया और वह सहमत हो गया। उसने टाल-मटोल किया और इसलिए एक कानूनी नोटिस जारी किया गया 23.02.1967 को उनसे अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए कहा गया। उसने (वादी ने) आज अदालत में आरओ संख्या के तहत प्रतिवादी को देय शेष राशि के रूप में 120/- रुपये जमा कर दिए हैं।''

उक्त कथनों को प्राण और सार में माना गया था, हालांकि वादी की ओर से ''तत्परता और इच्छा'' के अक्षरशः रूप में नहीं हो सकता है:

''10. यह सत्य है कि दलील में ''निष्पादन करने के लिए तत्पर और इच्छुक'' विशिष्ट शब्द नहीं हैं, लेकिन उपरोक्त दलील से, क्या यह पढ़ा जा सकता है कि वादी उस दायित्व के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था? दूसरे शब्दों में, क्या यह कहा जा सकता है कि उसने यह निवेदन नहीं किया है कि वह अपनी भूमिका निभाने के लिए ''तत्पर और इच्छुक'' है? अदालतें विशिष्ट पालन के दावे को विफल करने के लिए सार में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती हैं या ऐसी अति-तकनीकी व्याख्या नहीं कर सकती हैं जो उस उद्देश्य को विफल करती

है जिसके लिए उक्त अधिनियम अधिनियमित किया गया था। यह धारा विशिष्ट निष्पादन को लागू करने की मांग करने वाले वादी के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि उसे न केवल स्वच्छ हाथों से आना चाहिए, बल्कि यह दलील भी देनी चाहिए कि उसने दायित्व का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है या कर चुका है और करने के लिए तैयार और इच्छुक है। जब तक ऐसा न हो, धारा 16(सी) इस विवेकाधीन राहत के अनुदान में बाधा उत्पन्न करती है जैसा कि हमने कहा है, इसके लिए किसी विशिष्ट शब्द द्वारा दलील देना आवश्यक नहीं है, यदि किसी शब्द के माध्यम से यह तत्परता और इच्छा का पता चलता है वादी को अपने दायित्व का हिस्सा पूरा करना है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त धारा का अनुपालन नहीं हुआ है।''

इस न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 16 (सी) में संलग्न स्पष्टीकरण के बावजूद, वादी हमेशा अपने हिस्से का पालन करने की दृष्टि से संविदात्मक दायित्व के तहत अनुबंध के पालन के लिए प्रतिवादी को अदालत में जमा करने के लिए एक राशि दे सकता है।

उपरोक्त निर्णय को मोतीलाल जैन बनाम रामदासी देवी और अन्य में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा फिर से संदर्भित किया गया था, जो [2000] 6 एस.सी.सी. 420 में रिपोर्ट हुआ था। उस मामले

में भी इस न्यायालय ने वादी द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 6 से 11 किए गए कथनों पर विचार किया था।

"....9. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादपत्र में तत्परता और इच्छा का कथन कोई गणितीय सूत्र नहीं है जो केवल विशिष्ट शब्दों में होना चाहिए। अनुबंध के तहत दायित्वों के अपने हिस्से को पूरा करें जो वाद का विषय-वस्तु है, तथ्य यह है कि वे अलग-अलग शब्दों में हैं, बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद में वादी की तत्परता और इच्छा के विरुद्ध कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस मामले में वादपत्र के पैरा संख्या 6 से 11 स्पष्ट रूप से वादी की तत्परता और इच्छा को दर्शाते हैं। एकमात्र दायित्व जिसका उसे पालन करना था, वह था प्रतिफल की शेष राशि का भुगतान। यह कहा गया कि उसने प्रतिवादी से 8000/- रुपये की शेष राशि प्राप्त करने और विक्रय पत्र निष्पादित करने की मांग की। नोटिस के समय प्रतिवादी पटना (बिहार) में था और जब वह अपने स्थान पर वापस आया तो वादी ने उसके खिलाफ वाद दायर किया। अपने मामले के समर्थन में, उन्होंने पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के साक्ष्य पेश किए। वादी ने एक्सटेंशन 2 के निष्पादन के समय प्रतिफल का दो-तिहाई हिस्सा अलग कर लिया था।

ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह एक की शेष राशि का भुगतान नहीं करेगा। -संपत्ति को अपने पक्ष में करने के लिए 8000/- रुपये का तीसरा शुल्क।"

पुष्पारानी एस सुंदरम और अन्य बनाम पॉलीन मनोमानी जेम्स और बी अन्य के मामले में, (2002) 9 एस.सी.सी. 582 में कहा गया है:

"5.... अब तक यह दलील दी गई है कि वे अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तत्पर और इच्छुक थे, लेकिन हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह अपने आप में यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी तत्पर थे और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 (सी) के संदर्भ में इच्छुक। इसके लिए न केवल ऐसी दलील की आवश्यकता है, बल्कि इसके प्रमाण की भी आवश्यकता है। प्रथम दो परिस्थितियो में से प्रथम की जांच करते हुए, छूट दिए जाने के बाद वादी की तत्परता व इच्छुकता की परिस्थिति कैसे हो सकती है। यह अधिक से अधिक वादी की इस संपत्ति को पाने की इच्छा हो सकती है। हो सकता है कि ऐसी इच्छा के लिए यह वाद ऐसी याचिका दायर करते हुए दायर किया गया हो। लेकिन धारा 16 (सी) उक्त अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि केवल दलील पर्याप्त नहीं है, इसे साबित करना होगा।

6. अगली और एकमात्र अन्य परिस्थिति जिस पर भरोसा किया गया है वह 5000/- रुपये की निविदान के बारे में है, जो 02.03.1982 को की गई थी जो कि छूट दिए जाने से भी पहले थी। विक्रेता को अच्छी भावना में रखने के लिए विक्रेता के लिए ऐसा छोटा फीडर अक्सर बनाया जाता है। इस मामले में विक्रय के समझौते के निष्पादन के समय वादी द्वारा किया गया एकमात्र अन्य भुगतान 5000/- रुपये था। इस प्रकार, भुगतान की गई कुल राशि बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए शेष राशि से बहुत कम थी। इस प्रकार हमारी सुविचारित राय में उक्त दोनों परिस्थितियाँ एक साथ मिलकर इतना कमजोर तत्व है कि तत्परता और तत्परता की छवि बनाने के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16(सी) के लिए आवश्यक है कि न केवल तत्परता और इच्छा की दलील दी जाए बल्कि इसे साबित भी किया जाए। इसमें कोई विवाद नहीं है कि एक दलील के अलावा दो परिस्थितियों को छोड़कर इसे साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है। यह सच है कि केवल वादी का गवाह बॉक्स में न आना ही यह निष्कर्ष निकालने का कारक नहीं हो सकता है कि वह किसी दिए गए मामले में

तैयार और इच्छुक नहीं था, जैसा कि उच्च न्यायालय ने गलती से निष्कर्ष निकाला था..."

इसलिए, इस न्यायालय के निर्णयों में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए एक वाद में वादी को न केवल यह दलील देनी होगी कि वह हमेशा से था और यहां तक कि वाद दायर करने की दिनांक पर भी वह इसके लिए तैयार और इच्छुक था। अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करें, लेकिन उसे साबित भी करें। केवल कुछ असाधारण स्थितियों में, जहां अक्षरशः सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो, लेकिन वाद के दौरान रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के साथ-साथ वादी में दिए गए सभी कथनों को पढ़ने से तत्परता और इच्छा का पता लगाया जा सकता है। वाद में, उक्त आशय के लिए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16(सी) की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन किया गया माना जा सकता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि यहां पहले बताया गया है, हमारी राय है कि वादी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने कानून की आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से अनुपालन भी किया है।

किदार लाल सील और अन्य बनाम हरि लाल सील, [1952] एस.सी.आर. 179, जिस पर श्री अमरेंद्र सरन द्वारा भरोसा रखा गया है, का तत्काल मामले में कोई आवेदन नहीं है। उसमें, यह न्यायालय सिविल

प्रक्रिया संहिता के आदेश 34 को ध्यान में रखते हुए, वादी द्वारा दावा किये गए अनुतोष की कलात्मक शब्दावली से संबद्ध था। यह अभिनिर्धारित किया गया:

> ''लेकिन दोनों अनुतोषों को एक साथ पढ़ते हुए, मेरी राय है कि हालांकि दावा अमूर्त रूप से लिखा गया है, वादी ने वास्तव में प्रत्येक प्रतिवादी के खिलाफ ब्याज के साथ 40,253/- रुपये, 11-10 की सीमा तक बंधक डिक्री मांगी है। आदेश 34 के तहत किसी अन्य प्रकार की डिक्री नहीं दी जा सकती। इसलिए, हालांकि उन्होंने 'प्रस्थापन' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने असल में उस अनुतोष के बारे में पूछा है जिसके लिए एक सब्रोगी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत हकदार होगा।''

इस मामले का एक और पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वादी ने विक्रय का करार करने की दिनांक से लगभग छह वर्ष बाद वाद दायर किया। वह यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं लाया कि उसने कभी भी प्रतिवादी संख्या 1, संपत्ति के मालिक, से विक्रय के विलेख को निष्पादित करने के लिए कहा था। उसने तब वाद दायर किया जब उसे पता चला कि वाद की जमीन पहले ही अपीलार्थी के पक्ष में बेच दी गई थी। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 20 के संबंध में विवेकाधीन राहत प्राप्त करने के लिए वादी के लिए उचित समय के

भीतर अदालत से संपर्क करना अनिवार्य था। उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए, वादी विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं था।

वीरायी अम्मल बनाम सीनी अम्मल में [2002] 1 एस.सी.सी. 134 में विधि को निम्नप्रकार वर्णित किया है:

"11. जब, यह स्वीकार करते हुए कि, समय अनुबंध का सार नहीं था, अपीलार्थी-वादी को उचित समय के भीतर अदालत से संपर्क करने की आवश्यकता थी। चांद रानी बनाम कमल रानी, [1993] 1 एस.सी.सी. 519 में माननीय न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि अचल संपत्ति की बिक्री के मामले में अनुबंध के समय के सार के बारे में कोई धारणा नहीं है। भले ही समय अनुबंध का सार न हो, अदालत यह अनुमान लगा सकती है कि इसे उचित समय में पूरा किया जाना चाहिए यदि शर्तें (i) संविदा की स्पष्ट शर्तों से हों; (ii) संपत्ति की प्रकृति से; और (iii) आसपास की परिस्थितियों से, उदाहरण के लिए, अनुबंध करने का उद्देश्य। राहत देने के प्रयोजनों के लिए, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों से उचित समय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

12. के.एस. विद्यानदम बनाम वैरावन (1997) 3 एस.सी.सी. 1. में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 11, पैरा 14)

> ''यहां तक कि जहां समय अनुबंध का सार नहीं है, वादी को उचित समय के भीतर अनुबंध का अपना हिस्सा पूरा करना

होगा और अनुबंध की स्पष्ट शर्तों और संपत्ति की प्रकृति सहित सभी आसपास की परिस्थितियों को देखकर उचित समय निर्धारित किया जाना चाहिए।''

13. कानून में ''न्यायोचित'' शब्द का प्रथमदृष्टया अर्थ उन परिस्थितियों के संबंध में उचित है, जिनमें संबंधित व्यक्ति को उचित रूप से कार्य करने के लिए कहा जाता है, जो जानता है या जानना चाहिए कि क्या उचित था। ''न्यायोचित'' शब्द की सटीक परिभाषा देना अनुचित हो सकता है। कारण है कि व्यक्ति के स्वभाव और उस समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने निष्कर्ष में भिन्न होता है जिसमें वह सोचता है। शब्दकोष में ''न्यायोचित समय'' का अर्थ इतना समय होना है जो परिस्थितियों के तहत किसी विशेष मामले में संविदा या कर्तव्य के अनुसार सुविधाजनक ढंग से करने के लिए आवश्यक हो। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है, जैसे ही परिस्थितियाँ अनुमति दें। पी रामनाथ अय्यर की द लॉ लेक्सिकन में इसका अर्थ इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

''एक उचित समय, मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए सामान्य परिस्थितियों में एक उचित समय; जैसे ही परिस्थितियाँ अनुमति देंगी; परिस्थितियों में जितना आवश्यक हो उतना समय, सुविधाजनक रूप से वह करने के लिए जो अनुबंध के लिए आवश्यक है, किया जाना चाहिए 'सीधे' से कुछ अधिक दीर्घ स्थान; कार्य या कर्तव्य की

प्रकृति और उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इतनी समयावधि, जो उचित रूप से, और उचित रूप से, और उचित रूप से अनुमति दी जा सकती है या आवश्यक हो सकती है; ये सभी कमोबेश एक ही विचार व्यक्त करते हैं।"

लूई मारी डेविड और अन्य बनाम लुईस चिन्नाया अरोगियास्वामी और अन्य के मामले में (1996) 5 एस.सी.सी. 589 में न्यायालय ने विनिर्धारित किया:

"2. यह सुस्थापित विधि है कि जो पक्ष अदालत के न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का लाभ उठाना चाहता है और न्यायसंगत राहत के रूप में विशिष्ट पालन करना चाहता है, उसे स्वच्छ हाथों से अदालत में आना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो पक्ष झूठे आरोप लगाता है वह स्वच्छ हाथों से नहीं आता है और किसी प्रकार के न्यायसंगत अनुतोष को पाने का हकदार नहीं है..."

फिर भी, विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय अदालत दोनों ने वादी के पक्ष में अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इन्कार कर दिया। हमारी राय में, उच्च न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था कि नीचे के न्यायालयों द्वारा गलत कानूनी सिद्धांत पर विवेक का प्रयोग किया गया है।

ललित कुमार जैन और अन्य बनाम जयपुर ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (2002, 5 एस.सी.सी. 383 में इस न्यायालय ने कहा:

> "9. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय कुछ महत्वपूर्ण कारकों को संबोधित करने में विफल रहा है जो वादी को न्यायसंगत राहत से वंचित करता है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के तर्क को ध्यान में रखे बिना विचारण न्यायालय के एक सुविचारित फैसले को सरसरी तौर पर उलट दिया। हमारे विचार में, हमारे सामने बहस किए गए विभिन्न कानूनी मुद्दों पर विस्तार करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि कानून में वादी पंजीकरण और अपीलार्थी को टाइटल के हस्तांतरण से पहले विक्रय के अनुबंध को रद्द कर सकता है। हम आगे मान लेंगे कि वादी ने वास्तव में चैथे और अंतिम नोटिस दिनांक 03.07.1973 में निर्धारित समय की समाप्ति की दिनांक से अनुबंध को रद्द कर दिया है। यदि ऐसा रद्दीकरण या समाप्ति अनुबंध तथ्यों के आधार पर उचित नहीं है या वादी के आचरण को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 27 या 31 के तहत न्यायसंगत राहत से वादी को इन्कार किया जाना चाहिए, विचार के लिए कोई और प्रश्न नहीं उठता है। ऐसे

मामले में, अपीलार्थी की याचिका स्वीकार की जानी चाहिए और वाद खारिज किया जाना चाहिए।"

एक बार फिर निर्मला आनंद बनाम एडवेंट कॉर्पोरेशन (पी) लिमिटेड और अन्य [2002] 8 एस.सी.सी. 146 में इस न्यायालय ने कहा:

"6. यह सच है कि विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री देना न्यायालय के विवेक में निहित है और यह भी सुस्थापित है कि विशिष्ट निष्पादन की डिक्री देना हमेशा केवल इस कारण से आवश्यक नहीं है कि ऐसा करना कानूनी है। यह भी सुस्थापित है कि अदालत अपने विवेक से विशिष्ट निष्पादन की डिक्री देते या अस्वीकार करते समय एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अतिरिक्त राशि के भुगतान सहित कोई भी उचित शर्त लगा सकती है ..... "

एम वी. शंकर भट्ट और अन्य बनाम क्लाउड पिंटो चूंकि (मृत) द्वारा विधिक वारिस और अन्य [2003] 2 स्केल 124 भी देखें।

अब यह भी सुस्थापित हो गया है कि अपीलीय न्यायालय को आमतौर पर नीचे की अदालतों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

एआईआर 1967 एससी 249 उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बनाम सुंदर ब्रदर्स मामले में कानून निम्नलिखित शब्दों में बताया गया है:

‘‘8. यह अच्छी सुस्थापित है कि जहां भारतीय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालय में निहित विवेक का प्रयोग निचली अदालत द्वारा किया गया है, अपीलीय अदालत को उस विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए। अपीलीय चरण में उसके समक्ष उठाए गए मामले में अपीलीय अदालत को आम तौर पर केवल इस आधार पर अपील के तहत विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा कि यदि उसने वाद के चरण में मामले पर विचार किया होता तो यह एक विपरीत निष्कर्ष पर आ सकता था। यदि विचारण न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग तर्कसंगत रूप से और न्यायिक तरीके से किया गया है, तो यह तथ्य कि अपीलीय अदालत ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया होगा, विचारण न्यायालय के विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, यह आमतौर पर सही नहीं है अपीलीय अदालत को विचारण न्यायाधीश के विवेक के स्थान पर अपने विवेक का प्रयोग करना होगा; लेकिन यदि अपीलीय अदालत को यह प्रतीत होता है कि अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय ने अनुचित या मनमाने ढंग से कार्य किया है या प्रासंगिक तथ्यों की अनदेखी की है तो यह निश्चित रूप से सही होगा अपीलीय अदालत को विचारण न्यायालय के विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप करने के लिए। यह सिद्धांत सुस्थापित है, लेकिन जैसा कि चाल्स ओसेंटन एंड कंपनी बनाम जॉन्सटन 1942 एसी 130 पृष्ठ 138 पर, में विस्काउंट साइमन, एल सी द्वारा देखा गया है।

''अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए दिए गए आदेश को अपील की अदालत द्वारा उलटने का कानून सुस्थापित है, और जो भी कठिनाई उत्पन्न होती है वह केवल एक व्यक्तिगत मामले में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के आवेदन के कारण होती है।''

फिर भी गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, आदि बनाम गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर, सभा और अन्य, एआईआर (1980) एससी 1896 में विधि निम्नलिखित शब्दों में कहा गया है:

''73. जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उपचार असाधारण है और एंग्लो-सैक्सन विंटेज है, यह अंग्रेजी प्रक्रियाओं की कार्बन कॉपी नहीं है। अनुच्छेद 226 एक सौम्य सर्जरी है लेकिन लैंसेट वहां संचालित होता है जहां अन्याय होता है। जबकि पारंपरिक प्रतिबंध विकल्प की उपलब्धता की तरह हैं और न्यायिक शक्ति को आम तौर पर वहां जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जहां अन्य दो शाखाएं कदम रखने से डरती हैं, न्यायिक साहस को हतोत्साहित नहीं किया जाता है जहां घोर अन्याय भी सकारात्मक कार्रवाई की मांग करता है। अनुच्छेद 226 के विस्तृत शब्द निम्न लोगों की सेवा के लिए तैयार किए गए हैं उनकी शिकायतों में यदि विषय अदालत के प्रांत से संबंधित है और उपाय न्यायिक प्रक्रिया

के लिए उपयुक्त है। अनुच्छेद 226 के बारे में रवैया में एंग्लोफिलिक या एंग्लोफोबिक होने के बिना, एक देशी रंग है। इस न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने पर, हमें दोनों को सतर्क रहना होगा इस तरह आगे न बढ़ें जैसे कि अनुच्छेद 226 एक अपील जितना बड़ा हो और जहां गंभीर त्रुटि हुई हो वहां हस्तक्षेप करने से न चूकें। इसके अलावा, हम यहां उच्च न्यायालय के फैसले पर अपील करने के लिए बैठे हैं। और अपीलीय शक्ति तब हस्तक्षेप नहीं करती जब अपील किया गया आदेश सही नहीं होता बल्कि केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब वह स्पष्ट रूप से गलत हो। अंतर वास्तविक है, यद्यपि ठीक है।‘‘

उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसे तदनुसार अपास्त किया जाता है।

यह अपील सव्यय स्वीकार की जाती है। अधिवक्ता की फीस 5,000/- रुपये आंकी गई।

अपील स्वीकार।

नोटः- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास कुमार अग्रावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन एवं क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।